

एक नज़र

ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों का मामला

नई परंपरा से फैसला कराने के लिए चार मंत्रियों से मिले हरीश



विसंगतियों को दूर करने की मांग की।

चौधरी ने कहा कि 17 अप्रैल, 2018 में पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व सैनिकों के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर उपनियम जोड़ा, जिससे सभी वर्गों का आरक्षण प्रभावित हुआ है। नए नियम से भूतपूर्व सैनिकों का एक भी पद कम नहीं होगा। कैबिनेट में नियम पारित होने के बजाय डेफर होने पर हरीश चौधरी ने सीएम गहलोत पर हमला बोलते हुए इसे नई परंपरा शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्री अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कैबिनेट अप्रवृत्त ले सकती है, जबकि हमारी मांग को किसी भी स्तर पर कभी भी गैर वाजिब नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, अब सभी पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों सहित वरिष्ठजनों से व्यक्तिगत मांग की जाएगी कि वे आगे आकर युवाओं को न्याय दिलाने में मदद करें।

कुलदीप गुप्ता

जयपुर। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले पूर्व मंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी मंत्रियों से मुलाकात कर आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। चौधरी ने शनिवार को गहलोत कैबिनेट के मंत्री लालचंद कटारिया, डॉ बीडी कल्ला, शांति धारीवाल और परसादी लाल मीणा से मुलाकात की। इस दौरान हरीश चौधरी ने मंत्रियों को आरक्षण नियमों में विसंगतियों को समझाते हुए जल्द कैबिनेट बुलाकर



2018 से पूर्व कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं

हरीश चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक्स सर्विस मैन को लेकर 2018 से पूर्व कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। पूर्व सैनिकों को महिला आरक्षण की तर्ज पर होरिजेंटल रिजर्वेशन हो। उन्होंने कहा कि हमारा किसी के साथ संघर्ष नहीं है, इसमें असफल रहे तो आंदोलन को लोगों के बीच सड़कों पर लेकर जाएंगे। जायज मांग से पीछे नहीं हटेंगे। विसंगति से हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई प्रदेश में 50 से अधिक वाहन जब्त, एक गिरफ्तार



हिलव्यू समाचार

जयपुर। राज्य के माईस विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे तीन दिन के विशेष अभियान में पिछले 24 घंटों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए खनिजों के अवैध परिवहन में लिप्त 50 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके हैं। माईस, पेट्रोलियम और पीएचईडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में रात्रिकालीन गश्त के दौरान ही 25 से अधिक वाहनों को बजरी, मेसनरी स्टोन, क्वार्टज, ग्रीट, जिप्सम आदि का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। जयपुर वृत्त में ही पिछले 24 घंटों में 2 कंप्रेसर सहित 15

से अधिक वाहन जब्त किया जा चुके हैं। एफआईआर के साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्टोनमार्ट का उद्घाटन करते हुए जल्दी ही नई खनिज नीति, खनन श्रमिकों का सिलिकोसिस से बचाव, खनन कार्य में श्रमिकों के सुरक्षा उपाय और खनन क्षेत्र के लिए जल्द पर्यावरण स्वीकृति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाते हुए तुरंत प्रभाव से तीन दिन का विशेष अभियान चलाने का निर्णय करते हुए राज्य भर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात में गहलोत ने जारी किया कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र

भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे की काट के लिए गहलोत सरकार की योजनाएँ लागू करने का वादा

हिलव्यू समाचार

जयपुर। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार का विकास मॉडल सामने रखा है। शनिवार को कांग्रेस ने अहमदाबाद में जनता के सामने अपने शासन का विजन 'घोषणा-पत्र' के रूप में पेश किया। घोषणा पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश में लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम, दस लाख तक का मुफ्त इलाज, फ्री दवा और अंग्रेजी स्कूल खोलने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है कि सरकारी नौकरियों में कान्फ्लिक्ट व्यवस्था खत्म कर 10 लाख सरकारी नौकरियाँ दी जाएँगी। इसी तरह के वादों का घोषणा पत्र हिमाचल के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जनता के सामने रखा था। इसके बाद वहाँ भी इस स्कीम को लागू करने की मांग तेजी से उठी थी, जिसे लेकर भाजपा बैकफुट पर दिखाई दे रही थी।

ओपीएस, मुफ्त इलाज और बेरोजगारों को भत्ते का वादा



राहुल गांधी के आठ वचन पूरे करेंगे: अशोक गहलोत

गुजरात में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मेनिफेस्टो को महत्व देती है। सोनिया गांधी का सख्त निर्देश रहता था कि मेनिफेस्टो को प्रायोरिटी में रखें। राहुल गांधी ने जो वचन दिए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। छह लाख लोगों से पूछकर हमने यह मेनिफेस्टो बनाया है। बता दें, शुक्रवार को राहुल गांधी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करते हुए हिमाचल सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में इस लागू करने का ट्वीट किया था।

OPS बना बड़ा मुद्दा तीन और राज्यों ने किया लागू

गहलोत सरकार ने सबसे पहले ओल्ड पेंशन योजना लागू गैर भाजपा सरकारों के केन्द्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया। अब गैर भाजपाई दल इस स्कीम को भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मान कर इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, पंजाब की आप व झारखंड की सोरेन झामुमो सरकार ने इसे लागू कर दिया। कई राज्यों में कर्मचारी इस योजना को लागू करने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। हिमाचल और अब गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने इसी मुद्दे को भरपूर तरीके से उठाने की रणनीति अपनाई है। गहलोत की मुफ्त इलाज, ओल्ड पेंशन स्कीम आदि योजनाओं को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे की काट में इस्तेमाल कर रहे हैं।



#मॉडल_स्टेट_राजस्थान

बेहतर शिक्षा. नए अवसर.

सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म



- लगभग 1 लाख प्रतिभाशाली बच्चों को टैबलेट दिये जायेंगे।
- 69681 अध्यापकों की नवीन भर्ती लगभग 90 हजार शिक्षक पदों पर भर्तियाँ प्रक्रियाधीन।
- राज्य में 1658 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा।
- 10 हजार अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों का नवीन काडर।
- राज्य के सभी सेकेण्डरी स्कूलों को सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का निर्णय।
- प्रतिवर्ष 20,000 छात्राओं को स्कूटी वितरण।
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी योजना एवं गार्गी पुरस्कार के तहत 180.69 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी।
- आरटीई के तहत 1274.78 करोड़ रुपये की राशि का पुनर्भरण।

- यूनीक आईटी इंस्टीट्यूट - राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर में प्रस्तावित, कुल लागत 600 करोड़ रुपये
- मेडि-टेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकों पर रिसर्च के लिए - राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, जयपुर।
- जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब कुल लागत 200 करोड़ रुपये
- फिनिशिंग स्कूल: राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT), जयपुर
- गत 4 वर्षों में 211 नवीन महाविद्यालय खोले गए। इनमें से 94 कन्या महाविद्यालय।
- जिन विद्यालयों में 500 से अधिक छात्राएं वहां कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा।
- प्रतिवर्ष 200 बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन।
- गत 4 वर्षों में 42 नवीन कृषि महाविद्यालय।

राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किये गये हैं। इसके फलस्वरूप आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईएफटी, एफडीडीआई, एम्स, एनएलयू, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरिद्वेज जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आज राजस्थान में संचालित हैं। राज्य में तकनीकी और मेडिकल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले जाने की अनुमति से राज्य में शिक्षा का वातावरण बना है और विश्वविद्यालयों की संख्या 6 से बढ़कर 89 हो गई है। इससे राज्य के विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में जाने के स्थान पर प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। साथ ही मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के राजकीय शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का नामांकन छात्रों से अधिक हो गया है। बालिका शिक्षा के लिए किए गए कार्यों से आज हमारी बेटियाँ शिक्षा जगत में नए आयाम स्थापित कर रही हैं एवं उनमें गजब का आत्मविश्वास है।

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान



अधिक जानकारी के लिए 181 पर कॉल करें या <https://jankalyan.rajasthan.gov.in> पर विजिट करें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान



उपायुक्त सुरेश राव की झूठी की रिपोर्ट की प्रति छाया जो अदालत में पेश की गई।

पेज एक का शेष...

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम 5,
जयपुर महानगर द्वितीय

विविध दीवानी अपील संख्या...../2022

सियाराम दास, महन्त/पुजारी कनक बिहारी मन्दिर,
बनाम
राजेश सोनी व अन्य

विविध दीवानी अपील
जवाब मय लिखित बहस
मान्यवर महोदय,

रेसपोडेंट नम्बर 2 की ओर से जवाब मय लिखित बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाता है:-

1. यह कि उक्त उन्नवानी अपील मान्य न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसने आज की पेशी नियत है।
2. यह कि मंदिर के प्रथम तल एवं छत पर रिनोवेशन का कार्य करवाया जा रहा था। नगर निगम ने उक्त मंदिर में निर्माण कार्य सम्बंधी शिकायत मिलने पर मोक़े पर एक गार्ड लगाया गया था इसके बाद मोक़ा स्थिति की जांच करने पर पाया गया कि

मुख्य प्रतिनिधि (जयपुर/ए.सी.एम.फोर्ट)
उपायुक्त आदर्श नगर जोन प्रशासनिक शाखा (जयपुर/ए.सी.एम.फोर्ट) नगर निगम जयपुर, हरिद्वार

2

मंदिर में निर्माण कार्य नहीं करवाकर मात्र रिनोवेशन का कार्य मंदिर की आवश्यकतानुसार करवाया जा रहा था। मंदिर में किसी प्रकार का गैर अनुचित निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा था।

3. यह कि गोवर्धनपुरी कच्ची बस्ती में काफी अर्सा पूर्व से राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय अन्यत्र स्थान पर संचालित हो रहा है।
4. यह कि मोक़े की जांच करने पर यह स्थिति सामने आई कि कनक बिहारी जी का मंदिर काफी पुराना बना हुआ है तथा निर्माण कार्य काफी वर्षों पूर्व का कराया हुआ है तथा मोक़ा स्थिति अनुसार मंदिर परिसर में किसी प्रकार का नवनिर्माण नहीं कराया जा रहा है बल्कि पुराने में रिनोवेशन का कार्य करवाया जा रहा है।
5. यह कि मंदिर परिसर में मौजूदा निर्माण काफी पुराना होने के कारण भक्तों व जनता की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास मोक़े से खूबे हुये मात्र रिनोवेशन का कार्य करवाया जा रहा है कोई नवीन निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है।

मुख्य प्रतिनिधि (जयपुर/ए.सी.एम.फोर्ट) नगर निगम जयपुर, हरिद्वार

3

6. यह कि मंदिर परिसर में मात्र रिनोवेशन का कार्य करवाया जा रहा है जो कि नवनिर्माण की श्रेणी में नहीं जाने के कारण निगम के भवन निर्माण सम्बंध बने नियमों- उपनियमों के अनुसार किसी प्रकार की निर्माण अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है।

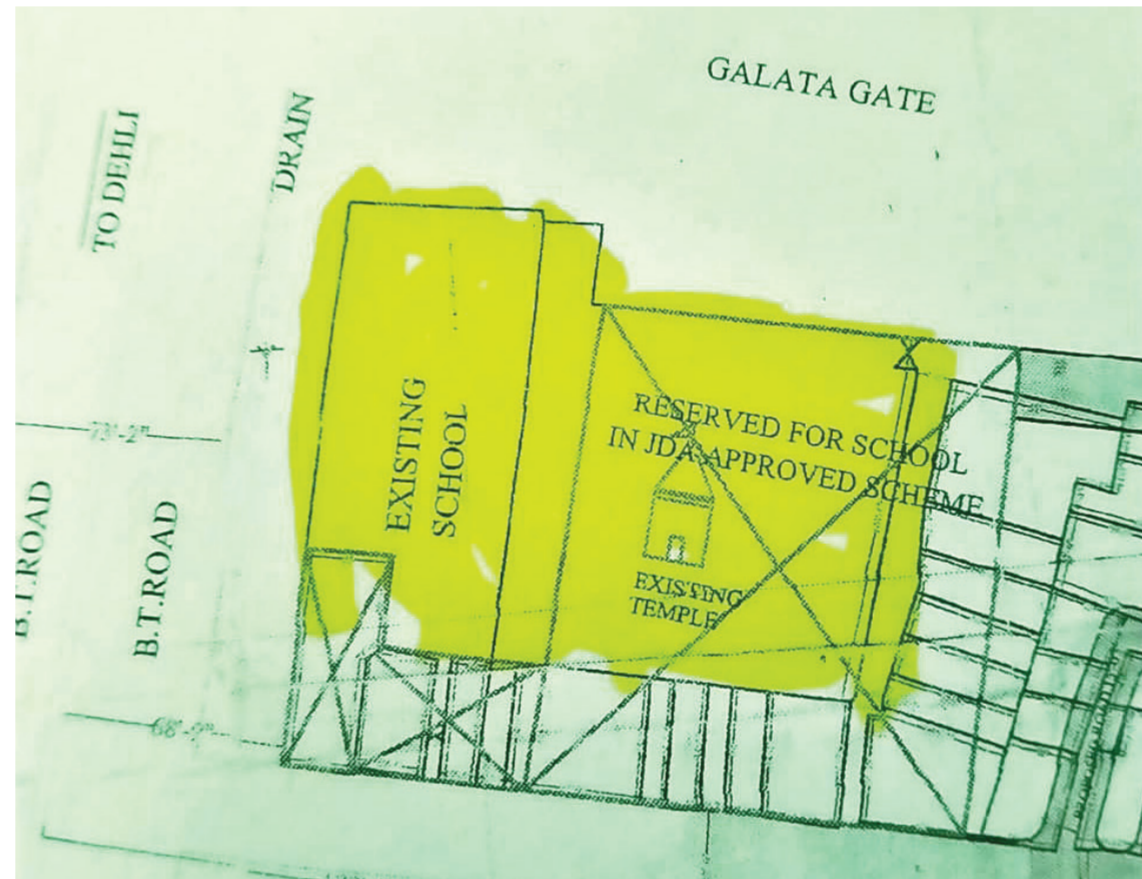
अतः जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत है।

जयपुर, रेसपोडेंट नं. 2
दिनांक:- 02/11/2022

उपायुक्त आदर्श नगर जोन प्रशासनिक शाखा (जयपुर/ए.सी.एम.फोर्ट) नगर निगम जयपुर, हरिद्वार

प्रति हस्ताक्षरित राख्य प्रतिनिधि प्रशासनिक शाखा (जयपुर/ए.सी.एम.फोर्ट) नगर निगम जयपुर, हरिद्वार

बेहद शर्मनाक बात है कि आदर्शनगर जोन के उपायुक्त सुरेश राव ने अदालत में झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पूरे प्रशासनिक सेवकों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए कि क्या एक आरएएस अफसर, जिम्मेदार पद पर बैठा प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार और अदालत की आँखों में धूल झाँक सकता है? सबसे बड़ी बात कि प्रतिउत्तर में उनका बचकाना जवाब आता है कि 'मैंने बिना देखे हस्ताक्षर कर दिए कई फ़ाइलें आती हैं टेबल पर', यह कहकर बचने वाले उपायुक्त क्या अदालत में पेश होने वाले कागज़ों पर भी आँख बंद कर हस्ताक्षर कर देते हैं? यह सरकार के लिए सोचनीय विषय है कि उनके प्रतिनिधि आँख बंद करके सेवाएँ देते हैं!



गलतागेट गोवर्धनपुरी राजकीय बालिका विद्यालय की ज़मीन जो नक्शे में खुद के अस्तित्व के होने की गवाही दे रही है जिसे शासन और प्रशासन का भ्रष्टाचार मिटा देना चाहता है।

02.11.22 काउंट के रिपोर्ट के साथ के अकाउंट लिखित बहस पेश की 15/11/22 के साथ सिमर 17-पेशी 05-11-22 को पेश की

प्रेम रसन ओझा
मुख्य प्रतिनिधि शाखा (जयपुर/ए.सी.एम.फोर्ट) नगर निगम जयपुर, हरिद्वार

मुख्य प्रतिनिधि (जयपुर/ए.सी.एम.फोर्ट) नगर निगम जयपुर, हरिद्वार

नयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश - 22

सियाराम दास महन्त/पुजारी कनक बिहारी मन्दिर, बनाम राजेश सोनी व अन्य

20/11/22

जयपुर नगर निगम

जेडीए द्वारा राजकीय बालिका विद्यालय हेतु आवंटित की गई ज़मीन जिसे अतिक्रमणकारी साधुसियाराम विधायक रफीक खान के इशारे पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण कर हथिया रहा है और आदर्शनगर जोन उपायुक्त सुरेश राव और निगम के जिम्मेदार अफसर इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं।

